इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 12 जुलाई 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------2
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा विनिमय----------5
सूक्ष्मवित्त -- ----------5
अर्थव्यवस्था ----------5
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------8
संस्थान समाचार----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक -मध्य-तिमाही नीति -16 जून 2011

नीतिगत उपाय

- पुनर्खरीद (Repo) दर 25 आधार अंकों (bps) की वृद्धि के साथ 7.5 % हुई।
- प्रत्यावर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 6.5 % हुई।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 6 % पर कायम रखा गया।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) बढ़ कर 8.5 % हुई।

मुद्रास्फीति

- वैश्विक पण्य कीमतें अब भी मुख्य बाहरी जोखिम बनी हुई हैं।
- घरेलू मुद्रास्फीति अब भी असहज स्तर पर कायम।
- ईंधन की कीमतों को अब भी कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों का निरूपण करना है।
- मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अब भी मुद्रास्फीति - विरोधी बना हुआ है।

- अप्रैल-मई के लिए थोक मूल्य सूचकांक संख्याओं में ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया जाएगा।

- शीर्ष (मुख्य)मुद्रास्फीति की दर अनुमानों के अनुरूप ऊंची बनी हुई है।

- विनिर्मित खाद्येतर मुद्रास्फीति से तीव्र अथवा व्यापक आधार वाली कमी का संकेत मिलता है।

वृद्धि

- मार्जिनों, ऋण वृद्धि से तीव्र अथवा व्यापक आधार वाली कमी का संकेत नहीं मिलता।

- वृद्धि में अल्पावधिक गिरावट मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अपरिहार्य हो सकती है।

- मौद्रिक प्रेषण बहुत सुदृढ़ हैं।

- ऋण की अपेक्षाकृत अधिक लागत ऋण वृद्धि को सीमित कर रही है, किन्तु वह काफी उच्च स्तर पर कायम है।

- चलनिधि की स्थितियां न तो अधिशेष वाली और न ही भारी घाटे वाली बनाए रखी जाएंगी।

- हाल की विश्वव्यापी स्थूल -आर्थिक घटनाएं घरेलू वृद्धि के समक्ष जोखिम उपस्थित करती हैं।

मुख्य घटनाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस वर्ष भी भारी नियुक्ति की तैयारी में

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने भर्ती अभियान को इस वर्ष भी जारी रखेंगे। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS), जिसने पिछले वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 48,000 रिक्तियां भरने में सहायता की थी, के निदेशक श्री एम. बालचन्द्रन इस वर्ष भी इसकी पुनरावृत्ति होने की आशा व्यक्त करते हैं। आगामी पांच वर्षों में जनशक्ति की भारी मांग को देखते हुए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS),बैंकिंग प्रणाली को 'नौकरी के लिए तैयार' अभ्यर्थी प्रदान करने की योजना बना रहा है।

झारखंड महिला सहकारी बैंक एक सफलता

महिलाओं के लिए एक सहकारी बैंक "दीदी बैंक" अपने उद्घाटन के एक वर्ष बाद झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के दूर-दराज़ के गांवों में एक सफलता बन गया है। 9 जुलाई, 2009 को पंजीकृत पूर्णत: महिला निजी सहकारी बैंक के पास उक्त विकास खंड में कुल 135 में से 87 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से 847 सदस्यों का रोस्टर मौजूद है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड सौदे को सुरक्षित बनाने के उपाय सुझाए

भातीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक कार्य दल ने कार्ड पर किए जाने वाले लेनदेनों को और सुरक्षित किए जाने की सिफारश की है। प्रारंभिक तौर पर बैंकों को प्रौद्योगिकी को सुरक्षित बनाते हुए, सभी हितधारकों के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबन्धन परंपराओं को सुधारते हुए और व्यापारी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हुए उनकी भुगतान से सम्बन्धित मौजूदा बुनियादी सुविधा को सुदृढ़ करना होगा। हालांकि, बैंकों द्वारा इन उपायों के कार्यान्वयन में दो वर्ष और लग सकते हैं।

धोखाधड़ियों को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियमों को कठोर बनाए

पिछले छ: महीनों में वित्तीय धोखाधड़ियों की श्रृंखलाओं से स्तंभित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में आंतरिक नियंत्रणों को कठोर बनाने के उपायों की घोषणा की है। उसने विदेशी बैंकों और निजी बैंकों से एक आंतरिक सतर्कता अधिकारी नियुक्त करने हेतु कहा है और धोखाधड़ियों को रोकने के लिए कठोर मानदंड निर्धारित किए हैं। ये मानदंड अदालती छानबीनों से प्राप्त प्रति-सूचना पर आधारित हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक जुलाई से 25-50 पैसे का कार्रवाई शुल्क लगाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई, 2011 से अंतर-बैंक खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए 25-50 पैसें का कार्रवाई शुल्क लागू किया है। जावक और वापसी लेनदेनों के लिए प्रवर्तक बैंक पर 25 पैसे लागू किए गए हैं। प्रवर्तक बैंक प्रत्येक जमा लेनदेन के लिए 25 पैसे और प्रत्येक नामे लेनदेन के लिए 50 पैसे का भी भुगतान करेगा।

बैंकों को 2 बीमा भागीदार रखने की अनुमति

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के एक पैनल ने यह सिफारिश की है कि एक बैंक को वर्तमान में केवल एक बीमाकर्ता के स्थान पर दो बीमाकर्ताओं के उत्पाद बेचने की अनुमति होनी चाहिए। ये गंठजोड़ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य को छोड़कर किसी भी दो बीमाकर्ताओं के समुच्चय अर्थात् दो जीवन बीमा क्षेत्र में और दो सामान्य बीमा क्षेत्र में, दो स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र - और निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) तथा कृषि बीमा निगम- के साथ हो सकती हैं। ये सिफारिशें अपेक्षाकृत अधिक बीमा पैठ एव गहनता, पॉलिसी धारक की सेवा करने के उच्चतर स्तर का लक्ष्य प्राप्त करने और उपयुक्त विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को विदेशों में शाखाएं खोलने से रोका

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को विदेशों में शाखाएं खोलने से रोक दिया है। हालांकि, विदेशों में पहले से शाखाएं रखने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को संशोधित दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्त पर उनके परिचालन को जारी रखने दिया जाएगा। तथापि, विनियामक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालय और सहायक कम्पनियां खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते इन सहायक कम्पनियों का उपयोग भारतीय परिचालन के लिए संसाधन जुटाने के साधन के रूप में न किया जाए।

सेबी ने बैंकरों के लिए मानदंड संशोधित किए

अनावश्यक नियमों एवं लालफीताशाही से बचने के उद्देश्य से बाज़ार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बैंकरों, डिबेंचर के न्यासियों तथा साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों को अपनी हैसियत एवं संविधान को बदलने हेतु उसका अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान कर दी है। अब केवल नियंत्रण में परिवर्तन की स्थिति में ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

आवास वित्त निगमों को अधिक प्रावधानीकरण करना होगा

आवास वित्त निगमों (HFCs) को अधिक प्रावधानीकरण का सामना करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) खुदरा अग्रिमों पर 0.4 % का मानक आस्ति प्रावधानीकरण लागू करने जा रहा

है। अब आवास वित्त निगमों को अपने अर्जक खुदरा गृह ऋण संविभाग के लिए अतिरिक्त पूंजी अलग कर रखनी होगी।

बैंकों की अनर्जक आस्तियां बढ़ सकती हैं : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कथन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एस. श्रीधर का कहना है कि उद्योग की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि ऐसी अपेक्षाकृत छोटी कम्पनियों, जिन्होंने उस समय उधार लिया था, जब दरें कम थीं, को दरों में वृद्धि तथा अतीत की तुलना में धन तक कम पहुंच के कारण अपने ऋणों को चुकाने में कठिनाई होगी।

बैंकों से वित्तीय समावेशन योजना के दूसरे चरण के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया

बैंक-रहित गावों को बैंकिंग के प्रसार क्षेत्र में लाना बैंकों के लिए ज्यादा कठिन हो गया है। मार्च 2012 तक उनके लगभग 73, 000 बैंक-रहित गांवों तक पैठ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद सरकार उनके द्वारा लगभग सभी 6 लाख गांवों को शामिल किए जाने की अपेक्षा रखती है। सरकार इस बात के प्रति उत्सुक है कि बैंक अप्रैल 2012 से आरंभ होने वाली उसकी वित्तीय समावेशन योजना (FIP) के दूसरे चरण में सभी ग्रामीण बस्तियों को शामिल कर लें, क्योंकि वह अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सभी लाभों को इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (EBT) के माध्यम से पहुंचाना चाहती है।

निर्यातकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक नकदीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तावित

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उसके साथ शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित कार्यविधियों को परी करने मे शीघ्रता लाने के लिए बैंक नकदीकरण प्रमाण पत्रों (BRC) के इलेक्ट्रॉनिक संवितरण को कार्यान्वित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ (IBA) और राष्ट्रीकृत बैंकों के शीर्ष प्रबन्धन के साथ बातचीत करने की तैयारी कर रहा है।

मीयादी जमाराशियों पर ऋण : उधारकर्ताओं के लिए सस्ता, बैंकों के लिए सुरक्षित

बैंकों की मीयादी जमाराशियों पर ऋणों को लोकप्रियता हासिल हो रही है। इन ऋणों में अप्रैल 2010 में लगभग 3 % के मुकाबले अप्रैल, 2011 में वर्षानुवर्ष आधार पर लगभग 25 % का उछाल आया है। निरपेक्ष रूप से बैंकों की मीयादी जमाराशियों पर ऋणों में 24 अप्रैल, 2009 और 23 अप्रैल 2010 के बीच वाली अवधि के महज 1,286 करोड़ रुपये की तुलना में 23 अप्रैल, 2010 और 22 अप्रैल, 2011 के बीच की अवधि में 11, 966 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। ब्याज दरों में वृद्धि की वर्तमान प्रणाली में ऐसे बैंक ग्राहकों, जिन्होंने पिछले कुछेक वर्षों में कमतर ब्याज दर वाली मीयादी जमाराशियों की संविदा कर रखी है, को आकस्मिकताओं के लिए और चलनिधि की स्थिति में निर्मित अस्थायी असंतुलनों को दूर करने के लिए इन जमाराशियों पर ऋण लेना लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक ऋण में अप्रैल में 55 % का उछाल

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र द्वारा ऋण के उठाव में वर्षानुवर्ष आधार पर अप्रैल 2010 की तुलना में अप्रैल, 2011 में पर्याप्त रूप से वृद्धि दर्ज हुई। अप्रैल, 2011 में वर्षानुवर्ष आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋणों में हुई 5 % की वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 15.1 % की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक रही। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋण में 23 अप्रैल, 2010 और 22 अप्रैल, 2011 के बीच वाली अवधि में 62, 244 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

जमाराशियों में बढ़ोत्तरी, बैंक ऋण में गिरावट

खुदरा और कारपोरेट जमाराशियों पर आकर्षक ब्याज दरों के कारण बैंक जमाराशियों में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही। 20 मई के दिन जमाराशियों में वार्षिक आधार पर 17.37 % की वृद्धि दर्ज हुई। खुदरा जमाराशियों में सुदृढ़ता आ रही है, क्योंकि बैंक अल्पावधिक जमाराशियों पर भी अपेक्षाकृत अधिक ब्याज प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, इस वृद्धि का कुछ अंश बैंकों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में जारी किए गए जमा प्रमाण पत्रों (CDs) के वापस लिए जाने से भी हो सकता है।

खुदरा निवेशक की रुचि लघु बचतों से हट कर बैंक जमाराशियों में

खुदरा निवेशक बैंक जमाराशियों पर मिलन वाली अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दरों के कारण लघु बचत योजनाओं - मुख्यत: डाकघर लिखतों में अपनी जमाराशियों के वृहत्तर अंश को बैंक जमाराशियों में विपथित कर रहे हैं। यह व्यवहार बचतकर्ताओं के बेहतर प्रतिलाभों की खोज में रहने तथा उनकी अधिशेष निधियों को बदलती दरों के अनुरूप परिवर्तित करते रहने की प्रवृत्ति को पुनर्बलित करता है। वर्ष 2010-11 में बैंक जमाराशियों के एक बार पुन: आकर्षक हो जाने के परिणामस्वरूप बकाया जमाराशियों में मार्च 2011 के अंत में वर्षानुवर्ष आधार पर लगभग 52 लाख करोड़ की वृद्धि हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने उधार जोखिम को अधिक संख्या में फैलाए

पिछले वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने जोखिमों को केवल शीर्ष उधारकर्ताओं को उधार देने की पूर्ववर्ती परंपरा के विरुद्ध अधिक उधारकर्ताओं में फैलाने के सुनियोजित प्रयास किए। अब उन्होंने अपने शीर्ष 20 उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा घटा दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), पंजाब नैशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जैसे बैंकों ने कुल रकम में मामूली वृद्धि परिलक्षित होने के बावजूद अपने शीर्ष उधारकर्ताओं की संख्या में

बहुत साधारण प्रतिशत की कमी ला दी है। बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने देयता पक्ष को जोखिम -रहित करने के लिए अपने शीर्ष 20 जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण में थोक जमाराशियों का कमतर आश्रय

लेते हुए कमी लाने के लिए भी इसी प्रकार के प्रयास किए हैं। हालांकि, वे इसके परिणामस्वरूप संसाधनों को कुछेक द्वारा ही हथिया लिए जाने और फलत: संकेन्द्रण जोखिम पैदा होने के प्रति भी सतर्कता बरत रहे हैं। जोखिम प्रबन्धन समितियां इस प्रकार के ऋण जोखिमों (exposures) की नियमित अंतरालों पर निगरानी कर रही हैं। अतएव, बैंक अपने संविभाग में देयताओं और आस्तियों को आवधिक आधार पर पुनर्संतुलित कर रहे हैं।

बैंकों की बाज़ार से उधार पर निर्भरता चलनिधि को प्रभावित कर सकती है

निधियों के गैर-पारंपरिक स्रोतों पर बैंकों की बढ़ती निर्भरता पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात के प्रति भयभीत है कि उधार ली गई मुद्रा का उच्च स्तर उनकी चलनिधि की स्थिति को प्रतकूिल रूप से प्रभावित कर सकता है। जमा संग्रहण में हुई लगभग 18 % की वृद्धि ऋण में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है। इस अंतर का निधीयन बाज़ार से ली गई निधियों (जमा प्रमाण पत्रों, निर्गमों एवं उधार राशियों) से किया गया, जो मार्च 2010 के अंत वाली स्थिति की तुलना में 34.5 % बढ़ गईं। बैंकों की दयेताओं में उधार राशियों और जमा प्रमाण पत्रों का अंश 2006 के लगभग 7.5 % से बढ़ कर 2011 में लगभग 10 % हो गया। विशेष रूप से अक्तूबर 2010 से फरवरी 2011 तक की अवधि, जिसके दौरान प्रणालीगत चलनिधि की स्थितियां दबावग्रस्त थीं, में ब्याज दरें बढ़ कर 9-10 % हो जाने के परिणामस्वरूप जमा प्रमाण पत्रों के निर्गम में बढ़ोत्तरी परिलक्षित हुई।

बैंकों ने चलनिधि समायोजन सुविधा के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये अधिक उधार लिये : प्रतिफल 6 सप्ताह के कमतर स्तर पर

अपेक्षाकृत अधिक अग्रिम कर बहिर्वाह की पृष्ठभूमि में भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) पटल से बैंकों की उधार राशियां हाल ही में तीन माह में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं। चलनिधि मांगों को पूरा करने के लिए बैंकों ने पुनर्खरीद चलनिधि समायोजन सुविधा के माध्यम से लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये - 18 मार्च, 2011 से सवाधिक रकम उधार लिया। इस बीच,इस अटकल के आधार पर कि भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी दर बढ़ाने की मुहिम को विराम देगा तथा कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से मुद्रास्फीति में कमी आएगी, प्रति-पुनर्खरीद पटल पर 200 करोड़ रुपये का केवल एक लेनदेन हुआ। 10 वर्षीय न्यूनतम दर वाले सरकारी बॉण्ड पर प्रतिफल घट कर छ: सप्ताह के न्यूनतम स्तर 8.19 % पर आ गया।

आधारभूत सुविधा कम्पनियों को आक्रामक रूप से उधार देने से बैंकों की आस्ति-देयता प्रोफाइल प्रभावित हो सकती है

भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों द्वारा आधारभूत सुविधा क्षेत्र को आक्रामक रूप से उधार देना जारी रखे जाने पर उन्हें उनकी आस्ति-

देयता प्रोफाइल का प्रबन्धन करने में कठिनाई हो सकती है। ब्याज दरों के विनियंत्रण, जो बैंकों को कम लागत वाली जमाराशियों पर ब्याज का उच्च दरों पर भुगतान करने हेतु विवश कर सकता है, समस्या को और भी गंभीर बना सकता है। मार्च, 2011 में आधारभूत सुविधा क्षेत्र में बैंकों का ऋण जोखिम (exposure) कुल ऋण बही का 14 % था, जबकि कुल जमाराशियों में बचत खातों का अंश लगभग 22 % था।

चलनिधि के बावजूद अल्पावधिक ऋण दरें गिरीं

अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण चलनिधि की स्थितियां खराब होने के बावजूद अल्पावधिक ऋण लिखतों की ब्याज दरों में गिरावट का क्रम जारी रहा। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस माह के प्रारंभ से जमा प्रमाण पत्रों और वाणिज्यिक पत्रों से सम्बन्धित दरों मे कम से कम 75-100 आधार अंकों की कमी आई है। बैंकों से कम मांग ने निवेशक की रुझान को पुनर्बलित किया तथा निकट भविष्य में चलनिधि की स्थितियों में अपेक्षित सुधार ने ब्याज दरों में कमी में योगदान किया। बैंक ऑफ इंडिया के उप महा प्रबन्धक, खजाना श्री पवन बजाज ने मत व्यक्त किया है कि " बैंकों ने थोक जमाराशियों से हाथ झाड़ लिया हैं, क्योंकि ऋण का उठाव कम है और उच्च लागत वाली जमाराशियां रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

विनियामकों के कथन

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मानव संसाधन से सम्बन्धित चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि "भर्ती, कौशलों का कोटि-उन्नयन और सांस्कृतिक सामंजस्य भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के समक्ष उपस्थित होने वाली प्रमुख चुनौतियां होंगे। प्रतिभा का अभिग्रहण, उसे टिकाए रखना तथा उच्चतर स्तरों पर पार्श्विक भर्ती उनके लिए भावी मार्ग होगी।" वर्तमान में भारत में बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन लोग नियोजित हैं, जिनमें से लगभग 75 % सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा नियोजित हैं।

बैंकों को कारबार संपर्की मॉडेल को हर हाल में व्यवहार्य बनाना चाहिए : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने विचार व्यक्त किया है कि "बैंकों को कारबार संपर्की (BC) मॉडेल की व्यवहार्यता और स्थिरता बढ़ाने के लिए उनके संगठनात्मक ढांचे का नवोन्मेषन करना होगा। "उन्होंने यह भी कहा है कि यह यथोचित रूप से स्पष्ट हो गया है कि उक्त

मॉडेल अनियत रूप से मापनीय नहीं है। हालांकि, इन चिंताओं के बावजूद यह एक अच्छी शुरूआत है। स्थानीय स्थितियों से उपयुक्त तालमेल बिठा कर इस सामान्य मॉडेल के मूलभूत अथवा नो फ्रिल्स खाते के माध्यम से वित्तीय प्रणाली तक कम से कम न्यूनतम पहुंच का लक्ष्य प्राप्त कर लेने की अत्यधिक संभावना है।"

मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत योजना की अवधि घटाएं : पैनल

मासिक आय योजना (MIS) और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की परिपक्वता अवधियों में कमी, लोक भविष्य निधि (PPF) में वार्षिक अभिदान की अधिकतम सीमा को 70, 000 रुपये से बढ़ा कर 1,00,000 रुपये किए जाने से सम्बन्धित ऊर्ध्वमुखी संशोधन तथा डाकघर बचतों की ब्याज दरों को 3.5 % से बढ़ा कर 4 % किए जाने से सम्बन्धित संशोधन उन महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) की व्यापक समीक्षा पर गठित समिति ने की है। उक्त समिति ने किसान विकास पत्र (KVP) को समाप्त किए जाने और अन्य योजनाओं को यथोचित आशोधनों के साथ जारी रखे जाने की भी सिफारिश की है।

अधिक अनर्जक आस्तियां भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रावधान बढ़ाने पर विवश कर सकती हैं

उधारदाताओं की बढ़ती अनर्जक आस्तियों पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि भारतीय बैंक जब तक अपने संविभागों का बेहतर ढंग से प्रबन्धन नहीं करते, उन्हें अशोध्य ऋणों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रावधानीकरण का सामना करना पड़ सकता है। एक अतिरिक्त चेतावनी के रूप में डॉ. चक्रवर्ती ने यह कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का वित्तीयन करने और उनके ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने का आह्वान किए जाने के बावजूद बैंकों ने अभी तक सूक्ष्म वित्त कम्पनियों को उधार देने की शुरूआत नहीं की है। बैंक लगभग 10, 000 करोड़ रुपये के ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक को निकट भविष्य में चलनिधि पर दबाव की आशा नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ ने कहा है कि शीर्ष बैंक को प्रचलित मांग दरों से यथा इंगित निकट भविष्य में चलनिधि पर किसी प्रकार के दबाव की संभावना नहीं दिखाई देती। इसके पूर्व बाज़ार के सहभागी अग्रिम कर बहिर्वाहों, जो 15 जुलाई, 2011 तक देय थे, की पृष्ठभूमि में प्रणाली में चलनिधि संकट निर्मित होने की आशा कर रहे थे।

वित्तीय स्थिरता के अधिदेश का मौद्रिक नीति के अनुरूप होना आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण के अनुसार "केन्द्रीय बैंकों को दिए गए वित्तीय स्थिरता के अधिदेश मुद्रास्फीति से सम्बन्धित प्रत्याशाओं और आर्थिक वृद्धि का प्रबन्धन करने के लिए मौद्रिक नीति के परिचालन के अनुरूप होने चाहिए। वैश्विक संकट ने इस मान्यता के समक्ष प्रश्नचिन्ह लगा दिया है कि मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता एक -दूसरे की पूरक होती हैं। इसके बजाय, वित्तीय स्थिरता मूल्य स्थिरता और स्थूल-आर्थिक स्थिरता वाले वातावरण में भी संकटग्रस्त हो सकती है।"

बैंकों के लिए सेवाओं को किफ़ायती बनाना जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने बैंकों से उनकी सेवाओं को किफायती बनाने का अह्वान किया है, क्योंकि केवल वैसा करके ही बैंक ग्राहकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ होंगे। इसके अलावा डॉ. चक्रवर्ती ने बैंकरों से वित्तीय समावेशन को वास्तविकता में परिणत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भी कहा है। विस्तार और व्यवसाय को बनाए रखना बैंकों के समक्ष उपस्थित दो चुनौतियां हैं। साहूकारों का वर्चस्व अब भी कायम है, क्योंकि बैंकिंग की पैठ केवल लगभग 40 % ही है।

बैंकों के लिए जोखिम निगरानी सक्षमताओं में सुधार लाना जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि बैंक बढ़ती ब्याज दरों की वर्तमान प्रणाली में आस्ति की गुणवत्ता में संभाव्य गिरावट को रोकने के लिए अपनी जोखिम निगरानी सक्षमताओं में सुधार लाएं। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती का कहना है कि जब आर्थिक स्थिति कठिन हो जाए, तो बैंकों को अपनी जोखिम प्रबन्धन सक्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। फिर उन्हें ऋण की गुणवत्ता के मोर्चे पर किसी समस्या का सामना नहीं करना होगा। ऋण उठाव की स्थिति ठीक होने के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों न कि केवल खुदरा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा और आधारभूत सुविधा क्षेत्र में बैंकों के ऋण जोखिम (exposure) के प्रति सतर्क हो गया है।

ग्रामीण अल्प आय वर्गों से बचत आकर्षित करें : पारस्परिक निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू पारस्परिक निधि उद्योग से विशेषत: ग्रामीण इलाकों के अल्प आय वर्गों, से बचतें आकर्षित करने हेतु यथोचित योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है। एक लम्बा पूर्ववृत्त होने के बावजूद निधि उद्योग के पास देश के सकल घरेलू उत्पाद की 10 % से कम आस्तियां मौजूद हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि "भारत में बचत को बढ़ावा देने में पारस्परिक निधियों की भूमिका निरंतर महत्वहीन बनी हुई है। अल्प आय वर्ग को आकर्षित करना ही एकमात्र वह मार्ग है जिससे वित्तीय बाज़ार में (निवेशकों की) सभी श्रेणियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है।"

विदेशी मुद्रा विनिमय

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**17 जून 2011 के दिन**	**17 जून 2011 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	**2**	**3**
कुल प्रारक्षित निधियां	13, 95, 599	310.562
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	12, 51, 794	278,610
ख) सोना	1, 09,832	24, 391
ग) विशेष आहरण अधिकार	20, 655	4, 597
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	13, 318	2, 964

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

जुलाई 2011 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.73350	0.6940	1.0890		

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष

अमरीकी डालर	0.73350	06943	1.089	1.542	1.952
जीबीपी	1.57875	1.4280	1.7970	2.1470	2.4730
यूरो	2.13750	2.165	2.375	2.597	2.789
जापानी येन	0.56000	0.393	0.426	0.481	0..561
कनाडाई डालर	1.85167	1...712	1.980	2.232	2.468
आस्ट्रेलियाई डालर	5.49000	5.009	5.130	5.390	5.510

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 2 बिलियन डालर से अधिक घट कर 310.50 बिलियन डालर हुई

लगातार तीन सप्ताह तक बढ़ने के बाद विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 2.401 बिलियन डालर घट कर 10 जून को समाप्त सप्ताह में 310. 503 डालर रह गईं। पूर्ववर्ती सप्ताह में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 2.689 बिलियन डालर बढ़ कर 310.503 बिलियन डालर हो गई थीं। विचाराधीन अवधि में प्रारक्षित निधियों में यह कमी मुख्यत: मुद्रा मूल्यांकन में हुए परिवर्तन के कारण आई है।

सूक्ष्मवित्त

स्वयं सहायता समूहों के लिए गुजरात सूक्ष्मवित्त के क्षेत्र में उतरा

गुजरात राज्य में सक्रिय नौ लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का सूक्ष्म वित्त सहलग्नता नेटवर्क लागू कर रहा है। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों को शामिल करते हुए देश का सबसे बड़ा सरकार-चालित सूक्ष्म वित्त सहलग्नता कार्यक्रम होगा।

स्वयं सहायता समूहों को 7 % पर बैंक ऋण प्राप्त होंगे

स्वयं सहायता समूह (SHG) अब पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश द्वारा यथा घोषित फसल ऋणों के समान 7 % पर बैंक ऋण प्राप्त करने में समर्थ होंगे। वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों को बैंक-सहलग्नता कार्यक्रम के तहत बैंक ऋण 12 % की दर पर प्राप्त होते हैं।

अर्थव्यवस्था

14

पूंजी अन्तर्वाह ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति संवेदी नहीं होते : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के एक अध्ययन में बताया गया है कि विदेशी पूंजी अन्तर्वाह देश में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति असंवेदी होते हैं। ब्याज दर में एक प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत में होने वाले निवल पूंजी प्रवाहों में केवल 0.05 प्रतिशत की वृद्धि होती है। घरेलू औद्योगिक और आर्थिक गतिविधि, शेयर से प्रतिलाभ, अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के कार्य-निष्पादन तथा विदेशी निवेशकों के जोखिम बोध ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जो विदेशी पूंजी आकर्षित करते हैं। इस टिप्पणी के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस आशय के भयों की खिल्ली उड़ा दी है कि मौद्रिक नीति को कठोर बनाए जाने से देश में निवल पूंजी के अन्तर्वाहों में कमी आ सकती है।

वित्त वर्ष 2012 में अर्थव्यवस्था के 8.5 % की दर से बढ़ने की आशा

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन को आशा है कि सेवा क्षेत्र और उद्योग के विस्तार के अनुसरण में भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2012 में 8.5 % की वृद्धि होगी। हालांकि, उन्होंने यह संकेत किया है कि वृद्धि के इस उल्लास में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक नहीं होगा। उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि "तथापि, 9 % और 9.5 % के बीच में वृद्धि का लक्ष्य रखना विवेकपूर्ण होगा। अर्थव्यवस्था को उसके आगे ले जाने से समस्याएं उठ खड़ी होंगी। " इसके पूर्व जारी वर्ष 2011-12 की अपनी मौद्रिक नीति में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 8 % की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया था, जो सरकार के 9 % के पूर्वानुमान से कम था।

अधिक मुद्रास्फीति कायम रहेगी, वृद्धि में कमी का जोखिम उपस्थित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विचार व्यक्त किया है कि तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल की कमी मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ववर्ती वृद्धि के पूर पास थ्रू का प्रभावी होना अभी तक शेष है। मई माह की थोक मुद्रास्फीति 9.06 % के अपेक्षित स्तर से अधिक रही - जिससे उन अर्थशास्त्रियों को निराशा हुई जो इस वर्ष के अंत तक 50-75 आधार अंकों की वृद्धि का पूर्वानुमान लगा रहे थे। अपनी तीसरी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात

का उल्लेख किया है कि "सरकार के अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक सहायता व्यय तथा मजदूरी एवं कच्चे माल की कीमतों में हुई वृद्धि से मुद्रास्फीति पर ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ने की संभावना है।" वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) में इस आशय का उल्लेख है कि मंद वैश्विक समुत्थान और घरेलू औद्योगिक वृद्धि में गिरावट के साथ मिल कर मौद्रिक नीति से सम्बन्धित कार्रवाइयों के प्रभावों ने वर्ष 2011-12 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के समक्ष अधोमुखी जोखिम उपस्थित कर दिया। वृद्धि की गति में यह मंदी वित्तीय क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त सरकारी व्यय, विशेषत: अनुदान बिल का प्रबन्धन वित्तीय समेकन की प्रक्रिया के समक्ष

चुनौतियां उपस्थित कर सकता है। यह समस्या राजस्व वसूलयों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली संतुलित वृद्धि द्वारा और भी गंभीर हो सकती है।

अहलूवालिया ने वित्तीय क्षेत्र के और सुधार प्रस्तावित किए

योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया यह महसूस करते हैं कि भारत को वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए और वित्तीय प्रणाली में मौजूदा नियंत्रणों को और कठोर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि "हमारे लिए वित्तीय प्रणाली को उदार बनाने की जरूरत है। वित्तीय उदारीकरण की उपयोगिता के बार में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जो वास्तव में सुस्थिर है। किन्तु सामान्यतया कोई उदार वित्तीय प्रणाली वृद्धि में योगदान करती है। निस्संदेह, एक ऐसा मोड़ आता है, जिसके आगे और अधिक वित्तीय उदारीकरण का को किसी प्रकार से प्रभाव नहीं होता। हमारे पास एक आदर्श प्रणाली मौजूद है तथा आगे बढ़ने के क्रम को जारी न रखना एक गभीर गलती होगी।"

भारी सरकारी उधार ऋण वृद्धि को 17-18 % पर सीमित रख सकते हैं : इक्रा की रिपोर्ट

भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) के अनुसार वार्षिक बजट में यथा पूर्वानुमानित भारी सरकारी उधार ऋण में केवल 17-18 % की वृद्धि होने दे सकते हैं, क्योंकि बैंकों को सरकारी प्रतिभूतिया (G-Sec) खरीदने के लिए निधियां अलग रखनी होंगी। वर्ष 2011-12 में बॉण्डों के माध्यम से केन्द्रीय और राज्य सरकारों की निवल उधार राशियों के (वर्ष 2010-11 में 4.1 लाख करोड़ रुपये की तुलना में) लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है । चूंकि बैंक इन बॉण्डों के लगभग 40 % का निधीयन करते हैं, उन्हें इस उद्देश्य के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपये की रकम अलग रखने की जरूरत होगी। यदि जमाराशियां 17 % बढ़नी हैं, तो शेष निधियां केवल 17-18 % की वृद्धि में सहायक होंगी।

नयी नियुक्तियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो कार्यपालक निदेशक नियुक्त किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दो मुख्य महा प्रबन्धकों, श्री पी. विजय भास्कर और श्री बी. महापात्र की कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्ति की है।

डॉ. प्रकाश बख्शी की नाबार्ड के नये अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति

डॉ. प्रकाश बख्शी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे नाबार्ड के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री आर. के. बम्मी की ऐक्सिस बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति

श्री आर. के. बम्मी ने ऐक्सिस बैंक के खुदरा बैंकिंग प्रभाग के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

श्री पटणी एचएसबीसी के प्रबन्ध निदेशक और इक्विटी प्रमुख के रूप में नियुक्त

एचएसबीसी बैंक ने श्री चेतन पटणी को प्रबन्ध निदेशक और भारत में अपने इक्विटी कारबार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	□□स संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
तमिलनाड मर्कंटाइल बैंक	एचडीएफसी आस्ति प्रबन्धन	एचडीएफसी के पास्परिक निधि उत्पादों के बैंक की चुनिंदा प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से विपणन हेतु
इंडसइंड बैंक	इलेक्ट्रा कार्ड सर्विसे□ (ECS)	उसके क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को मूल्य-योजित सेवाएं प्रदान करने हेतु। उसके क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए बैंक प्रौद्योगिकी एवं संसाधन सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (JICA)	भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा आरंभ की गई ऊर्जा बचत परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए, सिडबी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके और बैंकों, राज्य वित्त निगमों (SFCs) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को पुनर्वित्तीयन सहायता के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने हेतु।

भारतीय जीवन बीमा निगम	ऐक्सिस बैंक	उसके पॉलिसी धारकों और कर्मचारियों को सह-ब्रॉण्ड वाले कार्ड प्रदान करने हेतु। इस पर कार्ड धारक का फोटो और उसके ऊपार डिजिटल रूप में अधिमुद्रित हस्ताक्षर मौजूद होंगे। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध होगा तथा यह पॉलिसी धारकों को अन्य स्थानों से प्रीमियम की सुविधा प्रदान करेगा, इसप्रकार बैंक प्रभारों से बचत कराएघा।

फेडरल बैंक	वीसा	सभी फेडरल बैंक वीसा डेबिट कार्ड धारकों को यथार्थ समय में अंतरराष्ट्रीय विप्रेषण प्राप्त करने हेतु, इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक और सुरक्षित रूप से धनराशि उपलब्ध कराना

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक की भूमिका को समझने के लिए पाठकों को सूचना उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों के एक अंग के रूप में हमने पिछले अंकं में 'वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति' के विन्यास और संगठन की एक झलक प्रस्तुत की थी। इस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हम इसके नीचे जी 10 के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा 8 फरवरी 1999 को यथा अनुमोदित समिति को अधिदेश प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता के सम्बन्ध में उनके उत्तरदायित्वों को पूरा करने में केन्द्रीय बैंकों की सहायता करने के लिए यथोचित नीतिगत सिफारिशें परिष्कृत करने के उद्देश्य से वित्तीय बाज़ारो एवं प्रणालियों से सम्बन्धित मुद्दों पर निगरानी रखने और उनकी जांच करने हेतु केन्द्रीय बैंकों का एक मंच है। इस कार्य को पूरा करने में समिति वित्तीय बाज़ारों और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के समक्ष उपस्थित खतरों की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने तथा उन पर कार्रवाई करने में गवर्नरों की सहायता करने पर विशेष बल देगी। और अधिक विशिष्ट रूप से उक्त समिति के मूल उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :

- वैश्विक वित्तीय वातावरण में दबाव के संभाव्य स्रोतों की स्थूल-आर्थिक घटनाओं के मूल्यांकन सहित वित्तीय बाज़ारों और प्रणालियों में होने वाली घटनाओं पर एक नियमित एवं व्यवस्थित निगरानी व्यवस्था के माध्यम से पहचान एवं निर्धारण करने का प्रयास करना।

- वित्तीय बाज़ारों और प्रणालियों की कार्यपरकता एवं उनकी सुदृढ़ता के प्रति उनके विकास की सघन निगरानी और गहन विश्लेषण के माध्यम से केन्द्रीय बैंक के परिचालनों और

मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता के अपेक्षाकृत व्यापक उत्तरदायित्वों के विशेष संदर्भ में समझ को बढ़ाना।

- वैकल्पिक नीतिगत कार्रवाइयों के परीक्षण और तदनुरूपी नीतिगत सिफारिशों के कार्यान्वयन के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से कार्यरत एवं स्थिर वित्तीय बाज़ारो और प्रणालियों को बढ़ावा देना।

अपने विश्लेषण में समिति को मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता के बीच सम्बन्धों, संस्थाओं के बीच संलग्नताओं, अधारभूत सुविधाओं एवं बाज़ारों, वित्तीय मध्यस्थीकरण में वास्तविक एवं संभाव्य परिवर्तनों तथा बाज़ारों और प्रणालियों में निर्मित प्रोत्साहन ढांचों के प्रति विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। समिति को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक सहित केन्द्रीय बैंकों द्वारा सांख्यिकियों और अन्य सूचनाओं की डिज़ाइन, निर्मिति एवं प्रकाशन को बढ़ावा देते हुए और सरकारी तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों द्वारा यथोचित प्रकटन मानदंडों के अंगीकरण की सिफारिश करते हुए वित्तीय बाज़ारों एवं प्रणालियों की पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जहां प्रासंगिक हो, वहां समिति को सुदृढ़ सिद्धांतों और मानदंडों के सम्बन्ध में अंतरराष्ट्रीय सहमति विकसित करने में भी योदान करना चाहिए।

समिति को अन्य राष्ट्रीय, सार्वभौम, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सम्बन्धित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उत्तरदायित्वों के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विशेष रूप से इस प्रक्रिया की समग्र प्रभावशीलता को वढ़ाने के लिए इसे अपने कार्यकलापों का बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति और भुगतान एवं निपटान प्रणाली पर समिति जैसी बासेल- आधारित समितियों के साथ समन्वय करना चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

अवैयक्तिक सावधि जमा

कारपोरेट बैंक ग्राहकों द्वारा रखे गए सावधि जमा खाते जिन पर एक निश्चित समयावधि के लिए ब्याज की एक नियत रकम प्राप्त होती है। समय-पूर्व आहरण का जुरमाना वहन करने के जोखिम पर अग्रिम सूचना के बिना धनराशि आहरित नहीं की जा सकती। अवैयक्तिक सावधि जमा के उदाहरणों में मुद्रा बाज़ार जमा खातों, जमा प्रमाण पत्रों और निवेश खातों का समावेश होता है।

शब्दावली

मानक आस्ति प्रावधानीकरण

यह वह प्रावधान है जिसे बैंकों के लिए अपने लाभों से उन आस्तियों के समक्ष करना आवश्यक होता है, जो अर्जक (मानक आस्तियां) हैं तथा प्रावधानीकरण की दर विभिन्न प्रकार की आस्तियों के लिए अलग-अलग होती है, जो वर्तमान में वैश्विक बकाये के 19 % तक सीमित है।

19

संस्थान की गतिविधियां

नेतृत्व केन्द्र, आईआईबीएफ, कुर्ला में प्रशिक्षण

संस्थान द्वारा इजिप्ट के बैंकरों के एक दल हेतु लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तीयन पर पहले अध्ययन दौरे और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अपने नेतृत्व केन्द्र, कोहिनूर सिटी, कुर्ला में 20 जून से 24 जून 2011 तक किया गया। इस कार्यक्रम में 15 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

- भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत
  पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 /
  दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई
- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

संस्थान समाचार

परियोजना वित्त

संस्थान आईएफएमआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त में 15वें प्रमाण पत्र का आयोजन कर रहा है। बैच के लिए कैम्पस प्रशिक्षण 21 अगस्त से 27 अगस्त 2011 तक आयोजित होगा। विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

सूक्ष्म / सूक्ष्म शोध

संस्थान द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए सूक्ष्म / सूक्ष्म शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

सहयोगी / अध्येता सदस्यता

20

सहयोगी / अध्येता सदस्यता के लिए मानदंड संशोधनाधीन हैं तथा कोई नया आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा।

बाज़ार की खबरें

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18700
18500
18300
18100
17900
17700
17500

01/06/11 02/06/11 03/65/11 06/06/11 08/06/11 13/06/11 14/06/11 15/06/11
17/06/11 21/06/11 23/06/11 24/06/11 28/06/11

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

74.1
69.1
64.1
59.1
54.1

49.1
44.1
01/06/11 02/06/11 06/06/11 08/06/11 13/06/11 15/06/11 20/06/11 22/06/11 24/06/11 27/06/11 28/06/11

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- पर्याप्त पूंजी बहिर्वाहों के बीच डालर की विलंबित मांग पर जून के अंतिम सप्ताह में अमरीकी मुद्रा के समक्ष रुपया कमजोर पड़ गया।
- दो अन्य प्रमुख मुद्राओं में खरीदा-बेचा गया रुपया श्रेणीबद्ध रहा।
- रुपया लगातार दूसरे सप्ताह कमजोर हुआ।

भारित औसत मांग दरें

7.80
7.60
7.40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
01/06/11 03/06/11 04/06/11 06/05/11 11/06/11 14/06/11 16/06/11 18/06/11 20/06/11 22/06/11 24/06/11

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अप्रैल, 2011

- मांग दरें व्यापक तौर पर श्रेणीबद्ध रहीं।
- मांग दरें 6.59 और 7.71 के बीच मंडराती रहीं।
- माह के अंत में चलनिधि में थोड़ी कमी होती दिखाई पड़ी।

फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जुलाई, 2011